(vi) Financial assistance of Bihar for checking soil erosion in Samastipur.

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : समस्तीपुर जिले के दक्षिणी छोर पर स्थित पतसिया, सुल्तानपुर एवं चमथा पंचायात में पिछले 1980 से गंगा नदी का कटाव हो रहा है जिसके फलस्वरूप पिछले वर्ष तक पतसिया में 783, सुल्तानपुर में 2 (एवं चमथा में 295 परिवार विस्थापित हो चुके हैं। कटाव के परिणामस्वरूप अब तक दस हजार आबादी यत्र-तत्र रह रही है। तथा लगभग बीस हजार एकड़ उपजाऊ भूमि कट चुकी है। 1980-81 में बिहार राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा हेतु लगभग बारह लाख रूपये की योजना स्वीकृत की गई थी, परन्तु इसे कुछ विशेष सफलता नहीं मिली।

1981 दिसम्बर में उच्चस्तरीय तकनीकी समिति ने कटाव स्थल का दौरा कर पत्थर पाट कर इस कटाव से सुरक्षा का सुझाव दिया था। 1982 में राज्य सिंचाई तथा बीस सूत्री कार्यक्रम के मंत्रियों ने कटाव स्थल का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया किन्तु अब तक कोई सुरक्षात्मक कार्रवाई न हो सकी है। राज्य सरकार इस मद में उपयुक्त धन के अभाव में अक्षम है।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि वह बिहार राज्य सरकार के साथ सहयोग कर हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि का कटाव रोकने का सफल उपाय करे तथा हजारों परिवार को विस्थापित होकर आजीविका के साधन से वंचित होने से बचायें।

(vii) Need for giving clearance to Neorakhola Project and sanctioning requisite fund for its completion.

SHRI ANANDA PATHAK (Darjeeling): Sir, Civilian as well as Defence population in and around Kalimpong Town in th district of Darjeeling are experiencing great hardship due to want of drinking water. There is the shortage of nearly four lakh gallons of water per day. To alleviate this hardship and augment the water supply from a perennial jhoro called Neora Khola, a project report was prepared and finalised in consultation with the local army engineers. The approximate cost of the project is Rs. 16 crores. It was suggested that the capital cost of the project would be shared between the West Bengal Government and Defence Ministry. The recurring cost of this project is negligible as it is a gravity scheme.

The Project was sent to the Defence Ministry for sanctioning its share of cost. But subsequently, it appeared that the Ministry of Environment raised some objections to the implemention of this project.

Sir, according to the Project Report itself, no large scale denudation of forest in the vicinity of Neora Khola Catchment area is necessary as no big dam is required, simply a small weir would do to hold the water for syphoning of the same through pipes to Kalimpong and neighbouring area by gravitational pull and laying of such pipes need not cutting of trees unnecessarily.

This point has been made abundantly clear to the Prime Minister as well as the Union Deputy Minister of Environment by the Chief Minister of West Bengal.

I, therefore, urge upon the Government to give immediate clearance to the project and sanction the fund and make a statement in the House.

(viii) Demonstration by National Coordinations Committee of Indian Teachers Organisation in support of their demands.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : नेशनल कोर्डिनेशन कमेटी आफ इंडियन टीचर्स आर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में आज संपूर्ण

देश के कालेजों, विश्वविद्यालयों एवं स्कूलों के हजारों शिक्षक अपनी तेरह सूत्री मांगों को लेकर संसद के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगों में अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं के नियंत्रण के लिए संसद में पेश कानून को वापस लेने, शिक्षकों को ट्रेड यूनियन अधिकार बहाल रखने, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने, समान पाठ्यक्रम चलाने, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय वेतन नीति निर्धारित करने, उनके वेतनमान में संशोधन करने, स्कूलों के शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह कमीशन की नियुक्ति करने संबंधी प्रश्न शामिल हैं।

मेरा श्रम एवं शिक्षा मंत्री से अनुरोध होगा कि वे उनकी तेरह सूत्री मांगों को स्वीकार कर उनके असंतोष को दूर करें।

13.57 hrs.

Demands for Grants, 1983-84—(*Contd.*)

MINISTRY OF ACRICULTURE—(*Contd.*)

MR. DEPUTY SPEAKER : The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture.

Every Hon. Member from the ruling party should not take more than ten minutes each. There is a list of 17 Members from the ruling party, and if anybody takes more time, then other Members will not get a chance. In that case, you should not blame me.

Shri Panika to continue his speech.

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। यह बात सर्वविदित है कि कृषि मंत्रालय एक वृहत मंत्रालय है और इसके जिम्मे कृषि से संबंधित देश के सारे कार्यक्रमों को चलाने का काम सौंपा गया है। कृषि में उत्तरोत्तर विकास होता रहा है परिणामस्वरूप यदि आप देखें तो पायेंगे कि जब 1950-51 में प्लानिंग की प्रक्रिया शुरू हुई उस समय 508 मीट्रिक टन गल्ले का उत्पादन था लेकिन सरकार के प्रयासों के बाद 1981-82 में 1331 मीट्रिक टन उत्पादन हो गया जो सर्वोच्च स्तर पर है। इसलिए मैं मंत्री जी, मंत्रालय के सचिव, उनके अन्य सहयोगियों, कृषि वैज्ञानिकों को और देश के करोड़ों किसानों को बधाई देता हूं। जिनके प्रयास से यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। यही नहीं बल्कि कृषि पर जो कठिनाइयां आती रही हैं बाढ़, ओला, सूखा आदि उनका सामना करने के लिये कृषि मंत्रालय ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और राज्यों को समय-समय पर सुझाव दिये। नतीजा यह हुआ कि संकट की घड़ी में भी पिछले दिनों और इस समय भी हम सफलतापूर्वक उन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

13.59 hrs

[SHRI SOMNATH CHATTERJEE *in the Chair*]

मान्यवर, यह बात सही है कि इस वर्ष 1982-83 में देश के काफी हिस्से में, 15 राज्यों और एक संघीय राज्य में सूखे का भीषण प्रकोप है और लगभग 482 करोड़ हैक्टर भूमि सूखे से प्रभावित है और 53 लाख हैक्टर भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है। और बहुत से तटीय राज्य जैसे आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों के हिस्से तूफान से प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार 3 करोड़ सूखे से और 5 करोड़ बाढ़ से किसान प्रभावित हुए हैं। मैं पुनः एक बार सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अधिकतम राहत के लिये 738 करोड़ रुपए दिये और यही नहीं बल्कि सहायता के अतिरिक्त और भी जो विभागों से सहायता देने की बात होती है वह भी अलग से दी। और प्रधान मंत्री